चाय को उपभोक्ता वस्तुओं की सूची में से निकाला जाना

@2474. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चाय को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की सूची में से निकाल देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चाय ा उपयोग निम्न आय और उच्च आय ले, दोनों ही वर्गों के लागों द्वारा किया ाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार चाय के मूल्यों में स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दास मुंशी) : (क) सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आने वाली आवश्यक वस्तुओं की सूची में से चाय को निकालने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) देश में घरेलू खपत तथा निर्यात आवश्यकता दोनों के लिए चाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टी बोर्ड ने चाय का उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए कदम उठाये हैं । इनमें शामिल हैं :—

(1) चाय बागान वित्त योजना :— पुनर्रोपण, विस्तार रोपण, प्रतिस्थापन के लिए टी बोर्ड के ऋण ।

(2) चाय मशीनरी और सिंचाई मशीनरी की किस्त खरीद योजना :— सिंचाई मशीनरी और चाय मशीनरी के लिए टी बोर्ड के ऋण ।

(3) चाय क्षेत्र नवीकरण और चकबन्दी योजना :—नवीकरण छटाई और अतःसरण के लिए आर्थिक सहायता ।

(4) पुरानी झाड़ियों के पुनर्रोपण के लिए चाय पुनर्रोपण आर्थिक सहायता ।

(5) नए चाय एकक वित्त योजना :— अपरंपरागत क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए विस्तार के लिए विशेष ऋण और आर्थिक सहायता ।

(6) दार्जिलिंग ब्याज आर्थिक सहायत योजना :—उत्पादन की अधिक लागत के कारण परेशान दार्जिलिंग बागानों के पुनरुद्धार के लिए विशेष योजना । बैंकों और टी बोर्ड द्वारा 9,500 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता ।

(7) सिंचाई और निकासी के लिए बैंक ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना ।

(8) रोपण के विस्तार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना ।

(9) निवेश जमा खाता योजना :— चाय कम्पनियां अपने लाभ का 20 प्रतिशत नाबार्ड में कर मुक्त जमा करा सकती हैं, जो कि बाद में उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

FERA violation and excise duty evasion cases

2475. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several cases pertaining to FERA violations are pending with the Enforcement Directorate;

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1770, 25 नवम्बर, 1988 से स्थानान्तरित ।

(b) whether it is also a fact that several cases of violation under Excise Act, pending since 1980 are not yet completed;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) what action has been taken against the Reliance Industries Limited (RIL) for violation of the provisions under FERA and Excise Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE, (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (d) Informations being collected and will be laid on the Table of the House.

Hazardous chemical units in Gujarat

2476. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state whether Gujarat has the largest number of hazardous chemical units as per I.L.O. supported project report published in the Indian Express of the 17th October, 1988 and if so, what corrective steps the Central Government have taken or propose take in the matter?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): Yes, Sir. According to I.L.O. report there are 65 hazardous chemical units in Gujarat. The State Government has taken the following steps to deal with hazards posed by these units:

(1) Out of 65 units the on-site emergency plans have been prepared in respect of 60 units.

(2) The State Government has prepared off-site plans in respect of six districts where such units are concentrated.

(3) A coordination Committee to deal with chemical emergencies has been set up and a nodal department has been identified to deal with crisis situations.

(4) A Central scheme has been initiated to strengthen the management structure for handling of hazardous substances in the State.

(5) In service training for the officers and staff of Pollution Control Board and Inspectorate of Factories in the multi-disciplinary area of hazard and risk assessment is also imparted.

Sea beaches owned by Private Company

2477. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Central Government have recently removed embargo on owning sea beaches by private companies;

(b) whether a number of private companies approached the Central Government for permission to own sea beaches and if so, the names thereof;

(c) what are the reasons for removing such an embargo; and

(d) how far it will effect country's environment?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) The Government have not imposed any embargo on the ownership of sea beaches by private companies. The Government have issued guidelines for restricting certain activities within 500 metres of the high tide line, so as to protect the aesthetic, ecological and cultural values of the sea beaches.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.